

कोटे से अधिक बिक्री ने घटाई चीनी की मांग

न्यूनतम बिक्री
मूल्य में बढ़ोतरी
की उम्मीद में चीनी
मिलों ने पिछले
महीनों में अधिक
बिक्री की थी

[जयशी भोसले | पुणे]

देश में इस महीने चीनी की बिक्री रुक गई है। ट्रेड और इंडस्ट्री के सूत्रों ने बताया कि सरकार की ओर से तथ्य न्यूनतम बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी की उम्मीद में चीनी मिलों ने पिछले महीनों में अधिक बिक्री की थी और इससे सप्लाई बढ़ गई है। महाराष्ट्र के एक बड़े ट्रेडर ने कहा, '29 रुपये प्रति किलोग्राम पर बड़ी मात्रा में चीनी बेची गई थी क्योंकि ऐसी उम्मीद थी कि सरकार न्यूनतम बिक्री मूल्य को बढ़ाकर 31 रुपये प्रति किलोग्राम कर देगी। इससे सप्लाई में वृद्धि हुई है।'

केंद्र सरकार जून 2018 से मिलों के लिए मासिक बिक्री का कोटा तय कर रही है। सरकार ने मार्च के महीने के लिए 24.5 लाख टन का कोटा दिया है।

ट्रेड से जुड़े सूत्रों ने ईटी को बताया कि कई चीनी मिलों पिछले 10 महीनों में उन्हें आवंटित कोटा का 85 पर्सेंट ही बेच सकी है। बिक्री घटने के बीच उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की शुगर इंडस्ट्री एक-दूसरे पर न्यूनतम बिक्री मूल्य से कम पर चीनी बेचने का



आरोप लगा रही है। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्टरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रकाश नाइकनावारे ने बताया, 'मार्केट में अभी बड़ी मात्रा में चीनी आनी है। लेकिन मिलों को 15 मार्च के बाद गर्मी की डिमांड में तेजी आने की उम्मीद है।'

इंडस्ट्री के सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार मासिक कोटा से अधिक बिक्री करने वाली मिलों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव शुगर फैक्टरीज फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय खट्टल का कहना है कि केंद्र सरकार को चीनी मिलों के बिक्री के मासिक आंकड़े को सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने कहा, 'चीनी मिलों के बिक्री के आंकड़े अलग-अलग हैं। केंद्र सरकार को ये आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए।' सरकार की ओर से न्यूनतम बिक्री मूल्य बढ़ाने की उम्मीद के कारण चीनी मिलों पर कोटा से अधिक बिक्री करने का संदेह है।

Economic Diary

12/3/2019